KHAN GLOBAL STUDIES

The Most Trusted Learning Platform

SSC GD FOUNDATION 2024 -25

Bilingual

PRABHU SIR

आयोग Commission

आयोग Commission

आयोग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते है-There are mainly two types of commissions

1. संवैधानिक आयोग - महान्यायवादी, नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक , लोक सेवा आयोग , वित्त आयोग , निर्वाचन आयोग , पिछड़ा वर्ग आयोग आदि।
   Constitutional Commissions - Attorney General, Comptroller and Auditor General, Public Service Commission, Finance Commission, Election Commission, Backward Classes Commission etc.

2. गैर संवैधानिक आयोग - इसे दो वर्ग में बाट सकते है -Non-Constitutional Commissions - These can be divided into two categories -

A. संविधानेत्तर संस्था - योजना आयोग (NITI आयोग), विकास परिषद् , केंद्रीय सतर्कता आयोग , CBI , IB , RAW आदि।
   Extra-Constitutional Institutions - Planning Commission (NITI Aayog), Development Council, Central Vigilance Commission, CBI, IB, RAW etc.

B. सांविधिक या विधिक आयोग - मानवाधिकार आयोग , सुचना अधिकार आयोग आदि
Statutory or Legal Commissions - Human Rights Commission, Right to Information Commission etc.

वित्त आयोग Finance Commission (Art. 280)

15वां – NK सिंह
16वां – अरविन्द पनगढ़िया

गठन - 1 अप्रैल 1951
Formation - 1 April 1951

प्रथम अध्यक्ष - KC नियोगी
First Chairman - KC Niyogi

→ 26 जन 1950

संविधान लागू होने के दो साल के भीतर तथा प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा।
A Finance Commission will be constituted by the President within two years of the constitution coming into force and every 5 years.

यह अध्यक्ष सहित 5 सदस्यी होता है। It consists of 5 members including the chairman.

वित्त आयोग के कार्य Functions of the Finance Commission –

1. राज्यों के हिस्से का वित्तीय विभाजन करना। To make financial division of the states' share.

↳ राज्य को बजट मे कितना धन मिलेगा।

2. कमजोर राज्यों के लिए अनुदान राशि की मांग करना। To demand grants for weaker states.

3. मजबूत वित्तीय व्यवस्था के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा सौपे गए कार्यो को करना। To carry out the tasks assigned by the President in relation to a strong financial system.

वित्त आयोग के वर्तमान या 15 वें अध्यक्ष NK सिंह है। The current or 15th Chairman of the Finance Commission is NK Singh.

16 वें अध्यक्ष अरविन्द पनगड़िया होंगे। The 16th Chairman will be Aravind Panagariya.

अनु-315 → लोक सेवा आयोग Public Service Commission

संघ लोक सेवा आयोग Union Public Service Commission	राज्य लोक सेवा आयोग State Public Service Commission	संयुक्त सेवा आयोग Joint Service Commission
1→ संघ	राज्य	दो या दो से अधिक राज्यों
2:- Report - संघ - राष्ट्रपति	राज्य - राज्यपाल	संबंधित राज्य
3:- नियुक्ति/त्यागपत्र :- राष्ट्रपति	राज्यपाल	राष्ट्रपति
(4) कार्यकाल — 6 वर्ष 65 वर्ष तक	6 वर्ष 62 वर्ष	6 वर्ष / 62 वर्ष

कार्य Functions – Art. 320

1. प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाना।
   Organizing competitive examinations.
2. कर्मचारियों के पदोन्नति में सरकार की मदद करना।
   Helping the government in the promotion of employees.

अध्यक्ष व सदस्य का पद से हटाया जाना Removal of Chairman and Member from the post – Art 317 साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आरोप की जांच राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के द्वारा करवाएंगे यदि आरोप सही पाये जाते है तो राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा।

The President will get the allegations of proven misconduct or constitutional incapacity investigated by the Supreme Court. If the allegations are found to be true, the President can remove them from the post.

अनु 312 अखिल भारतीय सेवा All India Services –

यदि राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकेगा। If Rajya Sabha passes a resolution with a two-third majority, then the Parliament can create a new All India Service.

इस सेवा का अर्थ है सम्पूर्ण भारत में किसी भी राज्य में सेवा देना।This service means serving in any state in the whole of India. या भारत को सेवा देना।

वर्तमान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवा है At present there are 3 types of All India Services -

1. IAS → भारतीय प्रशासनिक सेवा – Indian Administrative Service
2. IPS → भारतीय पुलिस सेवा – Indian Police Service
3. IFS → भारतीय वन सेवा – Indian Forest Service

भविष्य में इंजीनियरिंग और चिकित्सा सेवा को शामिल किया जा सकेगा।
In future, engineering and medical services can be included.

राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य का पद से हटाया जाना –

Removal of the Chairman and Member of the State Public Service Commission from their posts-

साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आरोप की जांच राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के द्वारा करवाएंगे यदि आरोप सही पाये जाते है तो राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा। The President will get the allegations of proven misconduct or constitutional incapacity investigated by the Supreme Court. If the allegations are found to be true, the President can remove them from the post

यदि जाँच लंबित रहती है तो राज्यपाल पद से निलंबित कर सकेगा।

If the investigation remains pending, the Governor can suspend them from the post.

संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष First Chairman of Union Public Service Commission –

1. 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बार्कर थे। Sir Ross Barker on 1 October 1926.
2. स्वतंत्र भारत के एच.के.कृपलिनी थे। H.K. Kripalini of Independent India.

संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष - मनोज सोनी →
Current Chairman of Union Public Service Commission - Manoj Soni

→ मोहित अग्रवाल

निर्वाचन आयोग / चुनाव आयोग
Election Commission

निर्वाचन आयोग / चुनाव आयोग / Election Commission

गठन - 25 जन 1950

Formation-25 January1950

प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त - सुकुमार सेन

First Chief Election Commissioner-Sukumar Sen

वर्तमान में-25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार

Currently - 25th Chief Election Commissioner Rajiv Kumar

अनु 324 - राष्ट्रपति ,उपराष्ट्रपति , संसद और विधानमंडल के निर्वाचन का अधीक्षण ,निर्देशन ,और नियंत्रण करने के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा।There shall be an Election Commission to supervise, direct and control the elections of the President, Vice President, Parliament and Legislature.

जोकि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य उतने ही आयुक्तों से मिलकर बनेगा जितना राष्ट्रपति नियुक्त करें।Which shall consist of a Chief Election Commissioner and as many other Commissioners as the President appoints.

आरम्भ में यह एक सदस्यी था वर्तमान में 1989 से 3 सदस्यी है।Initially it was a single member body, presently it has three members since 1989.

नियुक्ति - राष्ट्रपति के द्वारा
Appointment - By the President

चुनव आयुक्तों की नियुक्ति की 3 सदस्यी चयन समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति करते है।The President appoints Election Commissioners on the recommendation of a 3-member selection committee. 2. Leader of the Opposition in the Lok Sabha - Member 3. Any Cabinet Minister nominated by the Prime Minister – Member

1. प्रधानमंत्री –अध्यक्ष Prime Minister - Chairman
2. लोकसभा के विपक्ष का नेता- सदस्य Leader of the Opposition in the Lok Sabha
3. प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री - सदस्य Any Cabinet Minister nominated by the Prime Minister

कार्यकाल – Tenure –

1. 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। 6 years or till the age of 65 years.
2. इससे पहले राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपना पद छोड़ सकता है।
   Before this, he can resign by submitting resignation to the President.
3. साबित कदाचार या संवैधानिक असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों के द्वारा दो तिहाई बहुमत से पारित प्रस्ताव पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा। On the basis of proven misconduct or constitutional incapacity, the President can remove the Chief Election Commissioner from the post on a resolution passed by both the houses of the Parliament with a two-thirds majority.

अन्य आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर राष्ट्रपति पद से हटा सकेगा। The President can remove other commissioners from the post on the advice of the Chief Election Commissioner.

निर्वाचन आयोग के कार्य Functions of Election Commission -

1. भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। Election Commission of India is a permanent constitutional body.
2. आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्य विधायकों और संसद के चुनावों की देखरेख करता है। The commission oversees the elections of President and Vice President, state legislators and Parliament.
3. चुनाव आयोग राष्ट्रपति को सलाह देता है कि क्या वर्तमान में राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में चुनाव कराए जाने चाहिए या नहीं। Election Commission advises the President whether elections should be held in states currently under President's rule or not.
4. परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्र के प्रादेशिक क्षेत्रों का चयन करना। Selecting territorial areas of constituencies throughout the country on the basis of Delimitation Commission Act.
5. मतदाता सूची तैयार करना और उसमें संशोधन करना Preparing and amending voter list

6. चुनाव की तिथि और कार्यक्रम तय करना Fixing the date and schedule of elections

7. विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना तथा उन्हें उनके चुनाव चिन्ह आवंटित करना। Recognizing various political parties and allotting them their election symbols.

8. चुनावों के दौरान टीवी और रेडियो जैसे विभिन्न मीडिया पर सभी राजनीतिक दलों से संबंधित नीतियों का प्रचार करे। Promoting policies related to all political parties on various media like TV and radio during elections.

9. सांसदों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना तथा विधायकों की अयोग्यता से संबंधित मुद्दों पर राज्यपाल को सलाह देना। Advising the President on matters related to disqualification of MPs and advising the Governor on issues related to disqualification of MLAs.

10. इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जारी करना Issuing Electronic Photo Identity Card (EPIC)

अनु 325 -किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकेगा। No person shall be disqualified from being included in the voter list on the basis of religion, race, caste or sex.

अनु 326 - मतदान का अधिकार Right to vote -

1. भारत का नागरिक हो। Must be a citizen of India.
2. न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर चूका हो। Must have attained the minimum age of 18 years.
3. मतदाता सूचि में नाम हो। Name should be in the voter list.
4. विधि द्वारा वंचित नहीं किया गया हो। Must not have been deprived by law.

KHAN GLOBAL STUDIES

Most Trusted Learning Platform

THANKS FOR WATCHING